(c) Distribution of certified and good quality seeds is primarily the responsibility of State Governments. The Government of India organises Zonal Seed Conferences before the commencement of *Kharif* and *Rabi* seasons every year in which the seed requirements of each crop of the State is assessed and arrangements for its supply from different sources is finalised.

Assistance for pilot projects for rice production in Andhra Pradesh

*170. SHRI PRABHAKAR RAO KALVALA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whethere there is any proposal under Government's consideration for the selection of some mandals/blocks in Andhra Pradesh for taking up pilot projects for increasing the production of rice;

(b) if so, the details thereof;

(c) the estimated financial assistance to be provided by the Centre for the special rice production programme in Andhra Pradesh; and

(d) by when the project is expected to be started?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BHAJAN LAL): (a) and (b) A Centrally Sponsored Special Foodgrains Production Programme-Rice (SFPP-Rice) is under implementation in 8 districts of Andhra Pradesh for increasing the production of rice. The districts covered under the programme are Chittoor, East Godavari, Khammam, Karimnagar, Nalgonda, Nellore, Warangal & West Godavari.

(c) For implementation of the programme during 1989-90 an outlay of Rs. 508 lakh has been sanctioned, comprising Rs. 381 lakh as Central assistance and Rs. 127 lakh as State's share.

(d) The project is already under implementation from 1988-89.

Setting up of National Consumer Disputes Redressal Commission

*171. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government have set up a National Consumer Disputes Redressal Commission;

(b) if so, the location thereof; and the names of the members of the Commission; and

(c) the functions of this Commission?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI SUKH RAM): (a) to (c) The National Consumer Disputes Redressal Commission, consisting of the following members, has already started functioning from 'A' Wing, 5th Floor, Janpath Bhavan, New Delhi:—

1.	Hon'ble Justice Shri V.B. Eradi a retired Supreme Court Judge	President.
2.	Smt. A.S. Vijayakar	Member.
3.	Shri Y. Krishan	Member.
3.	Dr. A.K. Ghosh	Member.
5.	Dr. Rais Ahmed	Member.

2. The National Consumer Disputes Redressal Commission has been set up in terms of clause (c) of section 9 read with sub-section (1) of section 20 of the Consumer Protection Act, 1986. It has jurisdiction to entertain complaints by a consu-

mer, a voluntary consumer association registered under the Companies Act, 1956 or under any other law for the time being in force or the Cental or any State Government which makes a complaint in respect of any goods or services and compensation, if any, claimed exceeds Rs. 10 lakhs and appeals against the orders of any State Commission. It can also call for the records and pass appropriate orders in any consumer dispute which is pending before or has been decided by any State Commission where it appears to the National Commission that such State Commission has exercised a jurisdiction not vested in it by law, or has failed to exercise a jurisdiction so created, or has acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity.

नई चीनी मिलों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत

*172. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई चीनी यूनिटों को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं ? क्या इनमें कोई संशोधन किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री सुख राम) : भारत सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये यूनिटों को लाइसेंस प्रदान करने और वर्तमान चीनी यूनिटों का विस्तार करने के लिए दिनांक 2-1-1987 के प्रैस नोट द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा की थी।

चीनी उद्योग तथा अन्य संबंधितों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की समीक्षा की गई और इनमें दिनांक 11-5-89 के प्रैस नोट द्वारा ढील दी गई। इन प्रैस नोटों की प्रतियां क्रमशः उपाबन्ध-1 और 2 के रूप में संलग्न हैं।

भारत सरकार

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

प्रैस नोट सं० 1

(1987 सिरीज)

विषय : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों का विस्तार करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत

सरकार ने गन्ने के और विकास के लिए संभाव्यता के साथ गन्ने की आश्वासित उपलब्धता के क्षेत्रों में चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और चीनी फैक्ट्रियों का विस्तार करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय किया है।

2. इस संबंध में अपनाए जाने वाले मुख्य मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत नीचे दिए जाते हैं :—

(1) नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए पहले सहकारी क्षेत्र को और बाद में सार्वजनिक क्षेत्र को लाइसेंस देने की छठी योजनावधि के दौरान अपनाई गई नीति सातवीं योजनावधि में भी जारी रहेगी। तथापि, ऐसे क्षेत्रों में जहां के लिए इन दोनों क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं, उस दशा में निजी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

(2) नयी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए मूल कसौटी प्रस्तावित फैक्ट्री स्थान के इर्द-गिर्द के सुसम्बद्ध क्षेत्र में गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता होगी। गन्ने की खेती के लिए संभाव्यता केवल अतिरिक्त घटक होगा।

(3) ऐसे स्थानों में जहां एक ही जिले में भारी संख्या में चीनी फैक्ट्रियां